

LOK SABHA

Wednesday, April 21, 1965/Vaisakha 1,
1887 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम के पहाड़ी जिले

+

- * 964 { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह तिद्धान्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछुवाय :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हेम राज :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ल० ना० भंजदेव :

- { श्री रा० बरुआ :
श्री प० ह० भील :
श्री कनकसबं ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कुछ पहाड़ी जिलों को स्वायत्तशासन देने के सम्बन्ध में हाल ही में आसाम के पहाड़ी जिलों के नेताओं का कोई शिष्ट मंडल प्रधानमंत्री से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन पहाड़ी जिलों को स्वायत्तता देने के प्रश्न का अध्ययन करने वाले प्रस्तावित आयोग की नियुक्ति का मामला किस अवस्था में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). जी, हां ; आसाम की आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फेंस का एक प्रतिनिधि मंडल दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में प्रधान मंत्री जी से मिला और अनु-रोध किया कि पहाड़ी जिलों को आसाम राज्य के ढांचे के अन्तर्गत कार्य करते हुए, जितनी अधिक सम्भव हो उतनी स्वायत्तता देने की योजना का विवरण तैयार करने के लिये एक आयोग को अविलम्ब नियुक्ति की जाये। अतएव आयोग नियुक्त कर दिया गया है और उसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। उस संकल्प की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है जिसके द्वारा आयोग का निर्माण किया गया। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4226/65]।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आसाम के इन पहाड़ी जिलों का का जो शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी से मिला था, उसने कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ सरकार के सामने रखी, जिन से विवश होकर सरकार ने ऐसा निर्णय किया।

श्री हाथी : उन्होंने जो कठिनाइयाँ रखीं, वे वहीं थीं, जोकि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखीं गई थीं अर्थात् उनका इकानोमिक डेवलपमेंट हो और उन को पार्टिसिपेशन इन ए ग्रेंटर मेजर फ़ार दी इकानोमिक डेवलपमेंट का अवसर दिया जाये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि क्या आसाम जैसे छोटे प्रदेश में इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयाँ बनाने से पृथकतावादी मनो-वृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ?

श्री हाथी : वह बात भी सामने आई थी। पहले तो वे लोग अपनी एक अलग स्टेट मांगते थे, लेकिन जवाहरलाल जी ने उनको कहा कि उनका हित आसाम के साथ रहने में ही है और इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिस में आसाम की युनिटी भी बनी रहे, केबिनेट फ़ार्म आफ़ गवर्नमेंट भी रहे, उन लोगों का विकास भी हो सके और उन को ऐसा महसूस हो कि वे भी इस विकास कार्य में सहयोगी हैं।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : सरकार ने जो आयोग नियुक्त किया है, उस को किन किन बातों पर विचार करने के लिए कहा गया है और वह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह इन्फ़ार्मेशन स्टेटमेंट में दी गई है।

श्री अ.क. रलाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कितना एरिया है, जिस के बारे में इस शिष्ट-मंडल ने बात-चीत की थी

और इस समय वहाँ पर किस प्रकार से शासन चलाया जा रहा है।

श्री हाथी : चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने यह सोचा है कि अगर इन जिलों को आटो-नोमी देने के वजाय इन को मिलिटारइजेशन किया जाये, तो उस से देश की रक्षा हो सकेगी, क्योंकि आटो-नोमी देने से लोगों में पद-लोलूपता बढ़ेगी और वे पारस्परिक झगड़ों में फंस जायेंगे, इसलिये वजाय आटो-नोमी देने के सैनिकीकरण किया जाये ?

श्री हाथी : आटो-नोमी का अर्थ कोई स्टेट के रूप में आटो-नोमी नहीं है। उस के बारे में इस स्टेटमेंट में कहा गया है :

...subject to the preservation of the unity of Assam, the continuation of a common legislature for the whole State of Assam and the maintenance of the Cabinet Government of the accepted form functioning on the basis of collective and joint responsibility to the State Assembly....

श्री बड़े : क्या यह सच है कि जैसे नागा-लैंड के पीछे फ़ारेन मिशनरीज काम कर रहे हैं, उसी प्रकार इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स की आटो-नोमी मांगने के पीछे भी क्रिस्टियन मिशनरीज काम कर रहे हैं ?

श्री हाथी : काम करने की अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमारे बात करने का सम्बन्ध है, हम इन डिस्ट्रिक्ट्स के प्रतिनिधियों के साथ ही बात करते हैं।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस विवरण में बताया गया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ पहाड़ी नेताओं ने जो बात-चीत की थी, उस के परिणामस्वरूप वे कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे थे। लेकिन उस विवरण में यह नहीं बताया गया है कि वे किस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। मैं यह जानना चाहता

हूँ कि पंडित जी के साथ बातचीत में पहाड़ी नेता जिस निष्कर्ष में पहुंचे थे, क्या सरकार उस से अगे जाने के लिये तैयार है या केवल उसी निष्कर्ष के अन्तर्गत रह कर कोई निश्चय किया जायेगा ?

श्री हाथी : जो बातचीत हुई थी और उससे जिस नतीजे पर पहुंचे थे, वह कमीशन के लिये बेसिस होगा। उस बातचीत में यह तय किया गया था कि आटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के लिये कुछ सबजेक्ट्स के विषय में अलग प्रबंध हो, जिस को स्काटिश पैटर्न कहते हैं, उस के आधार पर वहां का लेजिसलेटर काम करे, उन का एक क्रिनांसल एडवाइजर हो, ताकि वे लोग केबिनेट के अन्दर ही स्वतंत्र रीति से अपना काम अलग तौर पर कर सकें।

श्री विद्वनाथ पाण्डेय : पहाड़ी इलाकों का जो प्रतिनिधि मंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला था, क्या उसने यह अनुरोध भी किया था कि पहाड़ी इलाकों की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए उन का एक पृथक प्रान्त बना दिया जाये और उन को स्काटिश नमूने पर स्वशासन दिया जाये ?

श्री हाथी : जैसा कि अभी मैंने बताया है, पहले तो उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की थी, लेकिन पंडित जी ने उन को समझाया कि आसाम के साथ रहने में ही उनका फायदा होगा और तरक्की होगी। आसाम के साथ रहकर वे किस तरह अधिक से अधिक उन्नति कर सकते हैं, कमीशनस इसकी जांच करेगा।

Shri D. C. Sharma: The hon. Minister has said that this commission has been set up to explore ways of accelerating the economic development of these areas. But from the statement I find that this commission is also going to deal with the administrative, financial and legal measures necessary for giving effect to the scheme. May I know how the economic development of

these areas will be conditioned by the overall overhaul of the administrative, legislative and financial and other arrangements?

Shri Hathi: As the House knows, the financial powers and the economic development go side by side. If a project is sanctioned, but if it is not implemented properly for want of financial Powers that means that some change is necessary in that regard.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन चार जिलों की उन्नति के लिए यह मांग की गई है, उन की आबादी क्या है। क्या ये चारों जिले सीमा क्षेत्र से मिलते हुए हैं और क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि ये लोग आसाम सरकार से असंतुष्ट क्यों हैं ?

श्री हाथी : हर एक जिले की आबादी के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन उन्होंने यह मांग इसलिए की है कि वे मानते हैं और उन के दिलों में यह विचार है कि उन की जितनी प्रगति होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है।

गोआ , दमन तथा दीव का विकास

+

*947 { श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, दमन और दीव में वित्तीय वर्ष 1964-65 में औद्योगिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई ;